RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 30 JUNE TO 06 JULY 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 45 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी के चार साल पूरे : जानिए वित्त मंत्रालय ने बताए इसके क्या-क्या फायदे Page 3

चीनी निवेश के मुद्दे पर आमने-सामने आए भारत सरकार के दो विभाग Page 4

टाटा मोटर्स को इंडियन ऑयल से हाइड्रोजन आधारित 15 बसों का ऑर्डर मिला Page 7

editoria!

अर्थव्यवस्था से उम्मीदें

पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तरह इस वर्ष की पहली तिमाही भी महामारी से त्रस्त रही. दूसरी लहर तो आक्रामकता के हिसाब से पहली लहर से चार गुनी अधिक भयावह रही. इसके बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 11.5 फीसदी रहने का अनुमान है. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट ने यह भरोसा जताते हुए रेखांकित किया है कि ऐसा अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार की वजह से है. उल्लेखनीय है कि अप्रैल और मई में व्यापक संक्रमण के कारण एक बार फिर देश के बड़े हिस्से में पाबंदियां लगानी पड़ी थी. ऐसे में पहली तिमाही से ज्यादा उम्मीदें न होने पर भी अगर संतोषजनक बढ़ोतरी होती है, तो हम साल के बाकी महीनों को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं. काउंसिल का आकलन है कि परिस्थितियों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में वृद्धि दर 8.4 से 10.1 फीसदी के बीच रह सकती है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ सी रंगराजन का मानना है कि अगर महामारी की तीसरी लहर नहीं आती है, तो यह दर नौ फीसदी रह सकती है. हालांकि अनेक विशेषज्ञों की राय है कि पिछले साल की तरह अर्थव्यवस्था के संकुचन में जाने या वृद्धि दर के बहुत कम रहने की संभावना नहीं है. इसकी दो वजहें हैं. एक, पाबंदियों के हटने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के अनुभव हैं. ऐसा पिछले साल के आखिरी और इस साल के शुरुआती महीनों में देखा गया था. दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ जब छूटों का सिलसिला शुरू हुआ, तो जून में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं. दूसरी वजह यह है कि सरकार ने राहत पैकेज और बजट प्रावधानों के जरिये खर्च में वृद्धि की है, जिससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी सहयोग को जारी रखना होगा तथा उसकी मात्रा बढ़ानी होगी. केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में लगातार आश्वासन भी दिया जा रहा है, जो उत्साहवर्द्धक है. इसमें रिजर्व बैंक की भी बड़ी भूमिका है. लेकिन, हमें मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटे के रूप में इसके आर्थिक असर के लिए भी तैयार रहना होगा. ये असर स्वाभाविक ही हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी और बड़ी आबादी को राहत देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना ही होगा और बाजार में नगदी भी मुहैया कराने का सिलसिला भी जारी रखना है. इसके लिए अधिक उधार लेने और रिजर्व बैंक के सहयोग की दरकार है. पहली तिमाही के नतीजे जो हों, पर सभी आकलन भरोसा देते हैं. मॉनसून इस वर्ष भी सामान्य से अच्छा रहने की आशा है. विशेषज्ञों के अनुमान के आसपास ही रिजर्व बैंक का 9.5 फीसदी का आकलन है. केंद्र सरकार ने दूसरी लहर से पहले भरोसा जताया था कि विकास दर 11 फीसदी रह सकती है. बहरहाल, तमाम हिसाब के बावजूद यह तो तय है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है और महामारी से निपटते हुए अब इसे आगे बढ़ाना है.

SBI ने दिया झटका

अब चार बार से ज्यादा नकद निकालने पर लगेगा शुल्क, चेकबुक भी महंगी

नई दिल्ली। एजेंसी

बैंक अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में जहां पिछले साल ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा मिली थी, वहीं अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने एक जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू किए हैं।

यानी अब ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने और चेक के जरिए लेनदेन करने के लिए नए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। यह बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों पर लागू होगा। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, एक जुलाई से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों के लिए अतिरिक्त वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रभाव में आ रही हैं।

सिर्फ चार बार मुफ्त होगी कैश निकासी की सुविधा

एक जुलाई से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को बैंक के ब्रांच से या फिर एटीएम से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ चार बार ही मिलेगी। यदि ग्राहक चार बार से ज्यादा निकासी करते हैं, तो बैंक इस पर चार्ज वसूलेगा। ब्रांच चैनल या एटीएम में प्रति कैश निकासी पर 15 रुपये ते साथ जीएसटी वसूला जाएगा। एसबीआई के एटीएम के अलावा, अन्य बैंकों के एटीएम से निकासी पर भी इतना ही चार्ज लागू है। ध्यान रहे कि यह सीमा एटीएम और ब्रांच को मिलाकर है।

इतना महंगा पड़ेगा चेक का इस्तेमाल करना

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को एसबीआई एक वित्त वर्ष में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए आपको 40 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं 25 चेक वाली चेकबुक के लिए ग्राहकों से 75 रुपये के साथ जीएसटी वसूला जाएगा। इसके साथ ही 10 चेक वाली इमरजेंसी चेकबुक के लिए 50 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सर्विस चार्ज से छूट दी गई है।

क्या है एसबीआई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता?

एसबीआई और गैर-एसबीआई बैंक शाखाओं में बीएसबीडी खाताधारकों द्वारा गैर-वित्तीय लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। एसबीआई बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाते को जीरो बैलेंस बचत खाते के रूप में जाना जाता है। यह मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्गों के लिए है ताकि उन्हें बिना किसी शुल्क के बचत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन खाताधारकों को एक बेसिक रूपे एटीएम कम डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं लगाया जाता। इसके साथ ही निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता है। खाता बंद करने का शुल्क भी नहीं वसूला जाता है।

कच्चा तेल फिर तेजी की राह पर, अपने यहां कोई तब्दीली नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

कच्चे तेल का बाजार फिर उफान पर है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट ने 25 जून को समाप्त सप्ताह के लिए इंवेंट्री के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक इस सप्ताह वहां 8.153 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ। यह लगातार छठा सप्ताह है, जबकि वहां क्रूड ऑयल इंवेंट्री घटी है। वर्ष 2021 की शुरूआत से ही वहां कच्चे तेल के भंडार में 37 मिलियन बैरल की कमी हुई है। इससे मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल फिर चढ़ गया। इधर घरेलू बाजार में देखें तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे एक दिन पहले ही जहां पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की तेज बढ़ोतरी हुई थी वहीं डीजल भी 28 पैसे चढ़ गया था। नरम हुआ है। दिल्ली के बाजार में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 98.81 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा। यहां डीजल भी 89.18 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।

33 दिनों में ही 8.49 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

ऐसा देखा गया है कि अपने यहां जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 33 दिनों में ही पेट्रोल 8.49 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

33 दिन में 8.39 रुपये महंगा हुआ है डीजल

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने बीते 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने अंतिम बार 27 फरवरी 2021 को डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इसके बाद दो महीने से भी ज्यादा दिनों तक इसके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। चुनाव बीतने के बाद बीते 4 मई से अब तक रूक-रूक कर 33 दिनों में ही डीजल का दाम 8.39 रुपये प्रति लीटर चढ़ चुका है।

जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर-पीएम

नयी दिल्ली। एजेसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चार साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि यह व्यवस्था भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का एक पत्थर है। इसने करों की संख्या कम की है, अनुपालन बोझ के साथ ही आम आदमी पर कुल मिला कर करों का बोझ कम किया है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और संग्रह में खासी वृद्धि हुई है।'' ज्ञात हो कि पूरे देश में एक जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे।

महंगे पेट्रोल से राहत के लिए सरकार ने उठाया कदम

एथेनॉल मिश्रण को लेकर जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में जीवाश्म ईंधन ईकोसिस्टम में बदलाव के लिए रास्ता तैयार करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन ईंधन के रूप में पेट्रोल में 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को लेकर अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इस पर संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। अधिसूचना के मसौदा के अनुसार मौजूदा गैसोलीन उत्सर्जन मानकों के तहत स्पार्क इग्निशन इंजन युक्त एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण ई-12 और ई-15 से चलने वाले नए विनिर्मित वाहनों को प्रचलित गैसोलीन उत्सर्जन मानकों के अनुरूप मंजूरी होगी।

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार जल्द ही फ्लेक्स-फ्यूल इंजन पर फैसला लेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को अनिवार्य बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि मैं उद्योग के लिए एक आदेश जारी करने जा रहा हूं कि केवल पेट्रोल इंजन ही

नहीं होंगे, यहां फ्लेक्स-फ्यूल इंजन भी होंगे, जिससे लोगों के पास यह विकल्प होगा कि वह 100 प्रतिशत कच्चे तेल का या 100 प्रतिशत एथेनॉल का उपयोग करें। गडकरी ने कहा कि मैं अगले 8-10 दिनों में यह फैसला लूंगा और हम फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनिवार्य बनाएंगे।

गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता ब्राजील, कनाडा और अमेरिका में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे वहां के उपभोक्ताओं के पास 100 प्रतिशत पेट्रोल या 100 प्रतिशत बायो-एथेनॉल का उपयोग करने का विकल्प है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदूषण घटाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कहा था कि पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की समयावधि को घटाकर अब 2025 कर दिया गया है। सरकार ने पिछले साल पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2022 और 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को पाने के लिए 2030 का समय तय किया था।

गडकरी ने कहा कि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में बेहतर ईंधन है और यह एक आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी है। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को अनिवार्य बनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि हम एक मक्का अधिशेष, हम एक चीनी अधिशेष और एक गेहूं अधिशेष देश हैं। हमारे पास इन सभी खाद्यान्नों को सुरक्षित स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अबू धाबी पेट्रोरसायन केंद्र में निवेश के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये

नई दिल्ली। एजेंसी

रिलाइंस इंडस्ट्रीज ने अबू धाबी पेट्रोरसायन केन्द्र में निवेश के लिये मंगलवार को समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। निवेश राशि के बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं दी गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तेल से लेकर दूरसंचार सेवायें देने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की रुवाइस परियोजना में शामिल होगी। कंपनी ने कहा, ''अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने रिलायंस के रुवाइस, अबू धाबी में टीएजेडआईजेड में एक नए विश्व-स्तरीय क्लोर क्षार, एथिलीन डाइक्लोराइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) उत्पादन सुविधा में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।'' बयान में समझौते की रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बयान में कहा गया, ''यह समझौता महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल की बढ़ती मांग को भुनाने और वैश्विक औद्योगिक तथा ऊर्जा प्रमुख के रूप में एडीएनओसी और रिलायंस की ताकत को मजबूत करने में मदद करेगा।'' कंपनी ने कहा कि परियोजना का संचालन टीएजेडआईजेड औद्योगिक रसायन क्षेत्र में किया जाएगा, जो एडीएनओसी और एडीक्यू के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

ग्रीन एनर्जी के बावजूद पेट्रोल-डीजल पर रहेगा जोर

25-30 वर्षों तक बनी रहेगी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

अभी सरकार का पूरा जोर भले ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में पेट्रोल व डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन क्षमता पर रोक लगाने पर विचार चल रहा है। हकीकत यह है कि देश में पेट्रोलियम रिफाइनरी की क्षमता और बढ़ाई जाएगी। अभी देश की रिफाइनिंग क्षमता 24.6 करोड़ टन सालाना है, जिसे करीब दोगुना करने पर काम चल रहा है। देश के पश्चिमी तट पर एक नई विशाल रिफाइनरी लगाने को लेकर भी लगातार विमर्श चल रहा है। हालांकि सरकारी रिफाइनरीज के मौजूदा स्वरूप में काफी बदलाव हो जाएगा। इनके कारोबार के मिश्रण में होने वाले बदलाव के मद्देनजर इनके ढांचे में भी बदलाव की योजना सरकार तैयार कर रही है।

पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव तरुण कपूर ने दैनिक जागरण को बताया है कि पेट्रोल व डीजल की मांग भले ही अगले एक या दो दशकों में कुछ कम हो जाए, लेकिन दूसरे रिफाइनरी उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पेट्रो रसायन की मांग में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसके हिसाब से मौजूदा रिफाइनरी में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे रिफाइंड उत्पादों की मांग बढ़ने वाली है जिसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती है। साथ ही देश में रसोई गैस की मांग काफी बढ़ेगी।

अभी भी भारत अपनी खपत का 50 फीसद एलपीजी आयात करता है। हालांकि एलपीजी हर रसोई घर में पहुंच चुकी है। लेकिन जिन रसोई घरों में इनका रोजाना इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां आने वाले दिनों में इसकी खपत बढ़ेगी। तेल कंपनियों का कहा गया है कि वो अपने कारोबार में होने वाले संभावित बदलाव व बाजार में भावी संभावनाओं को देखते हुए रोडमैप बनाए।

सरकारी क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगले पांच वर्षों में अपनी क्षमता में 2.5 करोड़ टन का इजाफा करेगी। महाराष्ट्र में एक नई रिफाइनरी लगाने को लेकर बातचीत जारी है। यह देश की अभी तक की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। वैसे, भावी बदलाव को देखते हुए मौजूदा रिफाइनरीज में ग्रीन फ्यूल को लेकर भी अभी से कई तरह की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। हाल ही में देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक लाख मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की है।

इंडियन ऑयल रिफाइनरी विस्तार के साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। सोमवार को एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य का इंधन करार देते हुए कहा है कि जैसे-जैसे भारत में इसकी खपत बढ़ेगी, इसकी कीमत भी कम होती जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को तेजी से विस्तार करने पर काम कर रही है।

ऊर्जा दक्ष बनेगी कोल इंडिया, इस साल कार्बन उत्सर्जन में 60 हजार टन कमी लाने का लक्ष्य

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने अपने कामकाज को ऊर्जा दक्ष बनाने का निर्णय किया है और इस साल कार्बन उत्सर्जन में 60,000 टन से अधिक की कमी लाने की प्रतिबद्धता जतायी है। कोयला मंत्रालय के बयान के अनुसार देश में कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये तात्कालिक कदम के अलावा पंचवर्षीय योजना भी तैयार की है।

बयान में कहा गया है, ''...कोल इंडिया इस वर्ष के अंत तक 60,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता होगी।'' कोल इंडिया ने अपने परिचालन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपायों पर विशेष जोर दिया है और कंपनी अपनी सभी कोयला उत्पादक कंपनियों के खनन कार्यों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के विभिन्न उपायों के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

कोयला कंपनियां विद्युत आपूर्ति के कुशल प्रबंधन के अलावा ऊर्जा दक्षता के उपायों को अपने रिहायशी इलाकों, भवनों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि जैसे कई क्षेत्रों में लागू कर रही है। हालांकि, कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कमी भारी मशीनों के उपयोग (हेवी अर्थ मूविंग मशीन एचईएमएम) परिवहन, वेंटिलेशन, पंपिंग आदि जैसे खनन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी हैं। सीआईएल का जोर विभागीय स्तर पर या अनुबंध के आधार पर चल रहे एचईएमएम उपकरणों के विशाल बेड़े में बदलाव लाकर उन्हें डीजल की जगह एलएनजी से संचालित करने पर है। यह न केवल लागत में कटौती करने की दिशा में एक बड़ी सफलता होगी, बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। सीआईएल ने एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) का थोक उपयोग शुरू करने से पहले सीआईएल के कुछ खदानों में गेल के सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने की पहल की है। इसके अलावा कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये बिजली चालित वाहनों के उपयोग का निर्णय किया है। इसके तहत अगले पांच साल में सीआईएल के सभी खनन क्षेत्रों में लगभग 1,500 ई-वाहन का उपयोग किया जाएगा। इस साल के अंत तक लगभग 200 ई-वाहनों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। बयान के अनुसार सीआईएल अपने विभिन्न प्रतिष्ठानों में, लगभग 5,000 पारंपरिक एसी और अन्य उपकरणों की जगह ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाएगी। इसी तरह, ऊर्जा की बचत करने के लिए परंपरागत लाइट के स्थान पर करीब ढाई लाख एलईडी लाइट लगाई जायेंगी। कार्यालयों में पुराने पंखों को बदलकर उनकी जगह एक लाख से अधिक कम बिजली खपत वाले पंखों का उपयोग किया जाएगा। इन ऊर्जा दक्ष उपायों के जरिये कोल इंडिया ने अगले पांच साल में लगभग 2.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की योजना बनायी है।

जीएसटी के चार साल पूरे : जानिए वित्त मंत्रालय ने बताए इसके क्या-क्या फायदे

नई दिल्ली।एजेंसी

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के चार साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्रालय ने इसके फायदों के बारे में बताया। उसने बुधवार को कहा कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, कर की दरें में कटौती हुई और करदाताओं की संख्या में बढ़ी है। पूरे देश में जीएसटी एक जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क , सेवा कर , वैट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर समाहित थे। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बना दिया है। जीएसटी परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है।

जीएसटी (उएऊ) के तहत 40 लाख रुपये तक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को कर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। इसके स्कीम के तहत वे केवल एक प्रतिशत कर का भुगतान कर सकते हैं। के लिए एक साल में 20 लाख रुपये तक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है। इसके बाद एक साल में 50 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले सेवाप्रदाता कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। उन्हें केवल छह प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा।

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि जीएसटी उपभोक्ताओंऔर करदाताओं दोनों के अनुकूल है। जीएसटी से पहले उच्च कर दरों ने कर भुगतान करने को हतोत्साहित किया, हालांकि जीएसटी के तहत कम दरों ने कर अनुपालन को बढ़ाने में मदद की। अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं।''

वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी के तहत लगभग 1.3 करोड़ करदाताओं के पंजीकरण के साथ अनुपालन में लगातार सुधार हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने हैशटैग '4इयरऑफजीएसटी' के साथ ट्वीट करते हुए कहा कि जीएसटी ने उच्च कर दरों को कम किया। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी ने जटिल अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एक सरल , पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित कर व्यवस्था में बदल दिया है और इस तरह भारत को एक बाजार में एकजुट किया है।

भारत ने OPEC से कहा, कच्चे तेल कीमतें काफी चुनौतीपूर्ण, नीचे लाने की जरूरत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने ओपेक से कहा है कि कच्चे तेल का मौजूदा मूल्य काफी चुनौतीपूर्ण है और दरों को थोड़ा नीचे लाए जाने की जरूरत है। तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की बैठक से पहले मंगलवार को भारत ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि तेल की ऊंची कीमत का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जो उपभोग आधारित पुनरूद्धार की प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर पड़ने लगे।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत कीमत को लेकर संवेदनशील बजार है और वह जहां कहीं भी प्रतिस्पर्धी दर होगी, वहां से तेल खरीदेगा। पिछले सप्ताह ही मंत्री ने ओपेक से उत्पादन में कटौती को समाप्त करने का फिर से आग्रह किया था।मांग में सुधार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में तेजी आयी है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से चढ़े हैं। देश भर में ईंधन के दाम ऊंचे हैं और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपये लीटर को पार कर गया है। वहीं राजस्थान और ओडिशा में डीजल 100 रुपये लीटर से ऊपर निकल गया है। प्रधान ने बीएनईएफ शिखर सम्मेलन में कहा,''आज कीमत काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं अपने उत्पादक मित्रों से तेल की उपयुक्त कीमत का आग्रह कर रहा हूं। मंत्री ने कहा कि उनकी ओपेक महासचिव मोहम्मद बारकिंडो के साथ पिछले सप्ताह काफी सार्थक बातचीत हुई। ''अगले कुछ दिनों में ओपेक की बैठक होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि कीमत में कुछ नरमी आएगी। ओपेक, रूस और अन्य सहयोगी देशों की अगस्त और संभवतः उसके बाद के उत्पादन कोटा पर निर्णय को लेकर एक जुलाई को बैठक होनी है। ऐसी संभावना है कि ओपेक और उसके सहयोगी देश वैश्विक तेल मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को देखते हुए 500,000 से 7,00,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने को सहमत हों। उल्लेखनीय है कि मांग बढ़ने तथा आपूर्ति कम होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़कर 75 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर तक चली गयी है जो अप्रैल 2019 के बाद सर्वाधिक है। तेल के ऊंचे दाम मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा रहे हैं। प्रधान ने कहा कि ऊंची मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि के लिए चुनौती है।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद विदेशी मुंद्रा भंडार चार अरब डॉलर घटकर 603.93 अरब डॉलर पर

एजेंसी

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद गत 18 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.14 अरब डॉलर घटकर 603.93 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। इससे पूर्व 11 जून, 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.074 अरब डॉलर बढ़कर 608.081 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 18 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट रहा। यह कुल मुद्रा भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां आलोच्य सप्ताह के दौरान 1.918 अरब डॉलर गिरकर 561.540 अरब डॉलर रह गईं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां डॉलर में व्यक्त की जाती हैं पर इसमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और येन में होने वाले उतार- चढ़ाव का भी समायोजन किया गया है। पिछले सप्ताह में 49 करोड़ डॉलर की वृद्धि के बाद स्वर्ण भंडार भी आलोच्य सप्ताह के दौरान 2.170 अरब डॉलर घटकर 35.931 अरब डॉलर रह गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (घ्इ) में विशेष आहरण अधिकार (एऊं) 1.4 करोड़ डॉलर घटकर 1.499 अरब डॉलर रह गया। वहीं, आईएमएफ के पास देश का आरक्षित भंडार भी 4.6 करोड़ डॉलर कम हो कर 4.965 अरब डॉलर रह गया।

सरकार ने किसानों के लिए आत्मानिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने मंगलवार को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए 'आत्मनिर्भर कृषि ऐप' की शुरुआत की है। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म 'किसानमित्र' पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब 'आत्मनिर्भर कृषि ऐप' के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

यह ऐप - एंड्रॉइड और विंडोज संस्करणों में - किसानों, स्टार्ट-अप, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के लिए 12 भाषाओं में मुफ्त में उपलब्ध होगी। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने ऐप की पेशकश के दौरान कहा, ''किसानमित्र पहल के आत्मानिर्भर कृषि ऐप के साथ, किसानों के पास आईएमडी, इसरो, आईसीएआर और सीजीडब्ल्यूए जैसे हमारे शोध संगठनों द्वारा दी जाने वाली साक्ष्य-आधारित जानकारियां होंगी।''

सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए ऐप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बेंगलुरु स्थित इंडियन सेंटर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन (आईसीएसटी) के संस्थापक ट्रस्टी राजा सीवा इस ऐप और किसानमित्र के विकास में प्रमुख अंशधारकों में से एक हैं।

जुलाई महीने में इस-इस दिन बैंक रहेंगे बंद, यहां देखें पूरी लिस्ट

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जुलाई 2021 के महीने में अगर आप बैंक से संबंधित अपने कामों को निपटाना चाहते हैं तो आपको बैंक की छुट्टियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी की जाती है। हम आपको आज इन्हीं छुट्टियों के बारे में बताने वाले हैं। बता दें कि जुलाई महीने में बैंक 3 दिन बंद रहेंगे। इस कारण अपने बैंक संबंधित कामों को फटाफट से निपटा लें। रविवार को नियमित छुट्टी होती है और हर दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहता है। हालांकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण छुट्टियां भी अलग अलग होती है। केवल गेजेटेड छुट्टी में बैंकों में पूरे देश में एक साथ छुट्टियां होती हैं। बता दें कि इस महीने तीन दिन की छुट्टी में 2 छुट्टी शनिवार की है, साथ ही बकरीद के मौके पर भी बैंक की छुट्टी रहेगी। यानी की 10 जुलाई, 21 जुलाई और 24 जुलाई को बैंक बंद रहेंगे। कोरोना काल में ग्राहक डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। इसके लिए एँड समेत कई अन्य बैंकों द्वारा घर बैठे बैंकिंग की सुविधा को उपलब्ध कराया जा रहा है।

चीनी निवेश के मुद्दे पर आमने-सामने आए भारत सरकार के दो विभाग, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को बोली लगाने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार के दो विभाग आमने-सामने आ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडीचर (DoE) ने ऐसी घरेलू कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं में बोली लगाने की अनुमति दी है जिनका चीनी कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट है। लेकिन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) चाहता है कि यह छूट वापस ली जाए। उसे डर है कि इससे चीन की कंपनियां बैकडोर एंट्री कर सकती हैं।

सरकार ने पिछले साल भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के भारत में निवेश और सरकारी परियोजनाओं में भागीदारी पर रोक लगा दी थी। इसका मकसद खासकर चीन की कंपनियों को रोकना था। लेकिन DoE ने 8 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके कहा कि यह ऑर्डर उन घरेलू कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनका पड़ोसी देशों की कंपनियों के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) अरेंजमेंट है।

क्या है मामला

DPIIT ने 28 जून के अर्द को भेजे एक पत्र में कहा है कि उसे कई स्टेकहोल्डर्स की तरफ से ज्ञापन मिले हैं। इनमें आरोप लगाया गया है कि DoE का 8 जून का स्पष्टीकरण पिछले साल के ऑर्डर के मूल उद्देश्य और मंशा के खिलाफ है। DPIIT ने कहा कि इस तरह की छूट से पड़ोसी देशों की कंपनियों को अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी परियोजनाओं में बोली लगाने का मौका मिलेगा जो DoE के 23 जुलाई, 2020 के ऑर्डर का उल्लंघन है।

इंडस्ट्री चैंबर्स सीआईआई, फिक्की और एसोचैम, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, सेल्युलर मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साइंस, इंडिजीनस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड रिसर्च एक्सीलिरेटर और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकनॉमिक सर्विस लिमिटेड ने एक्सपेंडीचर विभाग के ऑर्डर पर चिंता जताते हुए ज्ञापन दिए हैं। DPIIT ने DoE को मामले की समीक्षा करने और फिलहाल ऑफिस मेमोरेंडम को होल्ड पर रखने का अनुरोध किया है।

चीनी कंपनियों को मौका

मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि DoE का ऑर्डर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के खिलाफ है। हमने वित्त मंत्रालय से इसे रोकने का अनुरोध किया है। DPIIT का कहना है कि DoE के मेमोरेंडम का मतलब है कि चीन की कंपनियां सरकारी खरीद में अपने प्रॉडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ इंस्टॉलेशन, मेंटनेंस, आफ्टर सेल्स सर्विस और इस तरह की दूसरी सर्विसेज के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कर सकती हैं। DoE के पिछले साल के ऑर्डर के मुताबिक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बिना इसकी अनुमति नहीं है।

वित्तमंत्री ने की मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठक

कहा- पूंजीगत व्यय को आगे बढ़ायें

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मंत्रालयों और संबंधित विभागों से पूंजीगत व्यय को कम करने के प्रयास करने को कहा। बुनियादी ढांचे के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए वित्तमंत्री ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की. इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर वित्तमंत्री की मंत्रालयों और विभागों के साथ यह छठी समीक्षा बैठक थी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रगति की समीक्षा करते हुए, वित्तमंत्री ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और इसे फ्रंटलोडिंग के लिए प्रयास करने के लिए कहा। साथ ही इस्पात मंत्रालय को कैपेक्स को फ्रंटलोड करने और सहायता प्रदान करके निजी निवेश की सुविधा बढ़ाने के लिए कहा।

सीतारमण ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से वित्तवर्ष 2021-22 के दौरान संपत्ति के मुद्रीकरण में तेजी लाने को कहा। दूसरी ओर, अंतरिक्ष विभाग को जहां भी संभव हो, घरेलू खरीद पर ध्यान देने के लिए कहा गया। सीतारमण ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि बुनियादी ढांचा खर्च केवल बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार का बजटीय खर्च नहीं है और इसमें राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचा खर्च शामिल है. इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से सरकारी व्यय भी शामिल है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इसलिए मंत्रालयों को सक्रिय रूप से अभिनव संरचना और वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्त पोषित करने पर काम करना है और बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को सभी सहायता प्रदान करना है।

वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रालयों को व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड का भी पता लगाने की जरूरत है। सीतारमण ने मंत्रालयों और उनके सीपीएसई को 31 जुलाई, 2021 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के बकाया की निकासी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने मंत्रालयों के सचिवों से बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए भी कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपलब्धि समय सीमा के अनुरूप हो। सीतारमण ने मंत्रालयों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करने के लिए भी कहा।

कोविड गाइडलाइन पालन करने वाले दुकानदारों का किया जाएगा सम्मान

व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा जागरूकता मुहिम

इंदौर। भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के महानगर मीडिया प्रभारी संतोष वाधवानी (रत्न विशेषज्ञ) ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से इंदौर में कोरोना पर विजय प्राप्त की है वह आम जनता की जागरूकता का परिणाम है , साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा सक्रियता से कॉविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए किए गए उपाय इसके लिए जिम्मेदार है । जैसा की आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है जिसको लेकर हमें अभी से सतर्क होना पड़ेगा ऐसे में अनेक दुकानदार कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करते हुए उनका सम्मान किया जाएगा। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्मल वर्मा (घूंगरू) एवं संतोष वाधवानी ने जानकारी दी कि भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ इंदौर के व्यापारियों में जन जागरण अभियान प्रारंभ करेगा और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ना आए इसके लिए व्यापारी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए उस हेतू सक्रियता से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।

सुधार के लिए उठाए गए कदमों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा: मुख्य आर्थिक सलाहकार

नई दिल्ली। एजेंसी

मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रह्मण्यम ने मंगलवार को कहा कि सरकार द्वारा पिछले एक साल में किए गए कई सुधारों से विदेशी निवेश सहित सकल निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इनमें आपूर्ति पक्ष की समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित सुधार भी शामिल हैं।

सुब्रह्मण्यम ने इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 पर वर्चुअल चर्चा में कहा कि ऐसे समय में जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एफडीआई में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है, भारत में एफडीआई बढ़ा है। महामारी के बीच भारत में एफडीआई बढ़ना इस बात का संकेत है कि विदेशी कंपनियों ने वह किया जिसकी वह बातें करती रहीं हैं। सेबी ने स्वतंत्र निदेशकों से जुड़े नियमों में किए ये बड़े बदलाव, इस तारीख से लागू होंगे

उन्होंने कहा कि विलय और अधिग्रहण में एफडीआई (FDI) बनाम ग्रीनफील्ड में एफडीआई का अंतर संगत है और 'यह तथ्य कि विलय एवं अधिग्रहण दूसरे देशों में उतना नहीं हुआ। लेकिन भारत में हुआ और उससे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी, भारत की वृद्धि की कहानी का परिचायक है।'

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी की गयी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2020 में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया। इस तरह से भारत एफडीआई हासिल करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश रहा। यह आंकड़ा सूचना एवं संचार उद्योग में किए गए अधिग्रहणों की वजह से हासिल हुआ। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला ऐसा देश है, जिसने पिछले डेढ़ वर्षों में कई सुधार किए जो कि मुख्य रूप से आपूर्ति पक्ष की कई समस्याओं को हटाने पर केंद्रित रहे। इसके साथ देश में निवेश का रास्ता साफ हुआ। सुब्रह्मण्यम ने कहा, 'श्रम सुधार, कृषि सुधार, एमएमएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की परिभाषा में बदलाव और सबसे ऊपर उद्यम नीति में निजी क्षेत्र पर ध्यान देना.. यहीं पर निजी क्षेत्र पर केंद्रित उद्यम नीति के संदर्भ में भविष्य के एफडीआई का रास्ता समझा जाना चाहिए।' गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (इएँ) नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में पीएसई में विनिवेश किया जाएगा। यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक साफ रोडमैप पेश करेगी।

प्रधान ने ओएनजीसी, ओआईएल को आगाह किया, खोजे गये क्षेत्रों से उत्पादन शुरू करें, अन्यथा छोड़ दें

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लि. (ओआईएल) को खोजे गये क्षेत्रों में उत्पादन शुरू नहीं होने को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि जो भी तेल और गैस क्षेत्र उनके पास हैं और जहां उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, उसे क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम के जरिये पूर्ण रूप से उपयोग में लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर सरकार इन क्षेखें को अपने नियंत्रण में लेकर नीलाम करेगी।

बीएनईएफ शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ऐसे समय जब देश तेल एवं गेस का शुद्ध रूप से आयातक है, कंपनियां संसाधनों को अनंतकाल तक अपने पास दबाये बैठी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि भारत 1990 के दशक से निजी और अन्य कंपनियों के लिये तेल एवं गैस क्षेत्र की नीलामी कर रहा है। इसके बाद भी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपारेशन (ओएनजीसी) और ओआईएल के पास कई साल से बड़ी संख्या में ऐसे क्षेत्र पड़े हैं।

प्रधान ने कहा, ''हमने उन्हें दो चीजें करने को कहा है। आप खुद से क्षेत्र के विशेषज्ञों और विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के

जरिये और फिर नये व्यापार मॉडल के जरिये तेल एवं गैस का उत्पादन करें। पर इतना तय है कि सरकार आपको अनंत काल तक संसाधनों को रोके रखने की अनुमति नहीं दे सकती।''

देश के सभी आठ अवसादी बेसिन क्षेत्रों की खोज और उसे उत्पादन में लाने वाली ओएनजीसी और ओआईएल देश में उत्पादित कुल तेल एवं गैस का करीब तीन चौथाई उत्पादन करती है। इन दोनों कंपनियों खासकर ओएनजीसी को खोजे गये क्षेत्रों से उत्पादन नहीं कर पाने को लेकर आलोचनाओं को सामना करना पड़ा है। प्रधान ने कहा कि भारत को अपने महत्वकांक्षी आथिक वृद्धि एजेंडे के लिये ऊर्जा की जरूरत है। ''हम आयात पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे संसाधन हैं, उसका पूरा उपयोग हो।''

उन्होंने कहा, ''इसीलिए हमने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नीतिगत दिशानिर्देश दिया है। या तो आप अपने दम पर नये भागीदारों के जरिये या नये आर्थिक मॉडल के आधार पर उत्पादन कीजिए, अन्यथा एक निश्चित समय बाद सरकार हस्तक्षेप करेगी और संसाधनों की नीलामी के लिये अपने अधिकार का उपयोग करेगी।'' इससे पहले भी प्रधान ने कहा था कि पेट्रोलियम मंत्रालय की तकनीकी इकाई हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को उन बड़े फील्डों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गयी है, जहां उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने 10 जून को कहा था, ''संसाधन किसी कंपनी का नहीं होता। वह देश का होता है। कंपनियां अनंतकाल तक उसे लेकर बैठी नहीं रह सकती। अगर कोई वहां से उत्पादन नहीं करता है, हम उसे नई व्यवस्था में लाएंगे।''

1 जुलाई से बदल रहे हैं ये 7 नियम, जानिए- आपकी जेब पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली। एजेंसी

हर माह की पहली तारीख को सरकार कई नियमों में बदलाव करती है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। जुलाई माह की पहली तारीख से भी कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपकी जेब से सीधा संबंध है। सरकार छोटी बचत स्कीम जैसे प्रॉविडेंट फंड, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से इनके ब्याज में बदलाव किया जा सकता है।

1 जुलाई से कारों के दामों में बदलाव किया जा सकता है। 1 जुलाई से हीरो की मोटरसाइकिल और मारुति के दामों में बदलाव किया जा सकता है। गैस सिलिंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। यह हर महीने की पहली तारीख को किया जाता है। ऐसी स्थिति में कल से घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में बदलाव किया जा सकता है। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है। उन्हें अब ज्यादा टीडीएस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक या केनरा बैंक में है तो आपको आईएफएससी कोड अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों को एटीएम विदड्राल पर चार्ज देना पड़ सकता है। यह एक जुलाई से लागू हो जाएगा। लेकिन यह तब लागू होगा जब आप एटीएम से 4 बार से ज्यादा पैसे निकालेंगे। यह चार्ज 15 रुपये का होगा लेकिन इसमें जीएसटी भी जोड़ा जाएगा. इसके साथ, आप चेक बुक लेते हैं तो आपको उसके लिए 40 रुपये देने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा

31 जुलाई तक लागू करें एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना' लागू करने का निर्देश दिया, जबकि केंद्र को प्रवासी श्रमिकों के बीच जब तक कोविड -19 की स्थिति जारी रहती है, मुफ्त राशन वितरण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केंद्र और राज्यों को खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर निर्देश जारी किए, जो कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण फिर से संकट का सामना कर रहे है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पोर्टल

पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की मदद से एक पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि संबंधित राज्यों में महामारी जारी रहती है, तब तक इसे जारी रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त में वितरण के लिए खाद्यान्न आवंटित करने के लिए कहा जब तक कि महामारी की स्थिति जारी रहती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए एक याचिका दायर की थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

RBI ने बैंकों को दिया करंट अकाउंट से जुड़ा ये बड़ा आदेश, 30 जुलाई तय की डेडलाइन

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने तमाम बैंकों

से सभी कंपनियों के उन करंट अकाउंट को छोड़ने और दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, जिनका एक्सपोजर रिजर्व बैंक की तरफ से निर्धारित कट-ऑफ से कम है। रिजर्व बैंक ने इसे लेकर करीब 15 दिन पहले ही एक लेटर भी बैंकों को भेजा था। करीब साल भर पहले रिजर्व बैंक ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था। इसकी वजह से बहुत सारे लुभावने ऑफर वाले करंट अकाउंट मल्टी नेशनल बैंकों से माइग्रेट होकर पब्लिक सेक्टर बैंकों और भारत के कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंकों के पास आ सकते हैं।

क्या है नया नियम

नए नियम के मुताबिक वह बैंक किसी कंपनी का करंट अकाउंट नहीं रख सकता है, जिसके पास कंपनियों को दी जाने वाली तमाम सुविधाओं का 10 फीसदी भी नहीं है। इन सुविधाओं में लोन, नॉन-फंड बिजनस जैसे गारंटी और डेलाइट ओवरड्राफ्ट या इंट्रा डे भी शामिल हैं। कुछ बैंक को अपने करंट अकाउंट अपने ही पास बनाए रखने के लिए अपनी सुविधाओ को 10 फीसदी के कटऑफ से बढ़ाने की कोशिश में भी लगे हैं।

कर्ज के एनपीए बनने की आशंका रहेगी कम

भारतीय स्टेट बैंक समेत कई पीएसयू बैंक मानते हैं कि नए नियम लागू होने के बाद काफी कुछ बदलेगा। गलत तरीके से कर्ज लेने वाली कंपनियों का अगर करंट अकाउंट और कलेक्शन अकाउंट कर्ज देने वाले बैंक के साथ होगा तो उसके लिए फंड्स को डायवर्ट करना मुश्किल होगा। ऐसे में कर्ज के एनपीए में तब्दील होने की आशंका भी कम रहेगी। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि नया नियम म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों पर लागू नहीं होगा।

बैंक कर रहे हैं अकाउंट शिफ्टिंग की तैयारी

रिजर्व बैंक ये देखकर बहुत ही उदास है कि बैंकों की तरफ से अकाउंट की शिफ्टिंग में काफी समय लग रहा है। हालांकि, इस देरी की एक वजह ये भी हो सकती है कि कई पीएसयू बैंक तकनीक के साथ तैयार ना हों। रिजर्व बैंक सीधे कंपनियों को ये आदेश नहीं दे सकता है जो बैंकों के साथ सालों से बिजनस कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बहुत से बैंकों और कंपनियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्हें भी समझ आ गया है कि ऐसा करना जरूरी है।

जुलाई में ये ग्रह बदलेंगे अपनी राशि जानें आपके जीवन पर प्रभाव

जुलाई माह 2021 में चार ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इन चार ग्रहों में बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह शामिल हैं। इनमें बुध ग्रह इस माह दो बार अपनी राशि बदलेंगे। माह की शुरूआत में पहले तो बुध अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे फिर अंत में इसी माह बुध चंद्रमा की राशि कर्क में जाएंगे। इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभावकारी रह सकता है। सूर्य देव इस महीने कर्क राशि में जाएंगे, तो वहीं शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी जुलाई माह में कर्क संक्रांति 16 तारीख को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की चाल का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। आइए जानते हैं जुलाई माह 2021 में ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनके प्रभाव

बुध का मिथुन राशि में गोचर

मिथुन राशि में बुध का गोचर जुलाई माह का पहला ग्रह परिवर्तन होगा। नवग्रहों के युवराज बुध देव 7 जुलाई 2021, बुधवार को वृष राशि से अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुधदेव इस राशि में 25 जुलाई रविवार तक स्थित रहेंगे। कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में मजबूत स्थिति में होता है। बुध के मिथुन राशि में गोचर से सभी राशियों पर इसका शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बुध देव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के तो वहीं मीन राशि में नीच के माने जाते हैं।

शुक्र का सिंह राशि में गोचर

शुक्र देव 17 जुलाई को कर्क राशि से सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र 11 अगस्त, 2021 बजे तक स्थित रहेंगे। इसके बाद यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणना के

अनुसार, शुक्र ग्रह सिंह राशि में रहते हैं तो वे बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं क्योंकि सूर्य देव और शुक्र ग्रह के बीच शत्रुता का भाव है। शुक्र देव को इस संसार के समस्त भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। यह वृष और तुला राशि का स्वामी है। शुक्र देव कन्या राशि में नीच के तो मीन राशि राशि में उच्च के माने जाते हैं।

मंगल का सिंह राशि में गोचर

मंगल ग्रह 20 जुलाई 2021 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में ये 6 सितंबर 2021 तक रहेंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सभी नौ ग्रहों का अपना स्वभाव और अलग-अलग कारक तत्व होते हैं। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को सभी ग्रहों का सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा मंगल ग्रह को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह शुभ भाव में होते हैं ऐसे लोग काफी बुद्धिमान, प्रतापी और ऊर्जावान होते हैं। ज्योतिष में मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना जाता है। मंगल ग्रह कर्क राशि में ही नीच के और मकर राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं।

बुध का कर्क राशि में गोचर

संचार और वाणी के कारक बुध देव 25 जुलाई रविवार को अपनी स्वराशि मिथुन की यात्रा समाप्त करके चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को ये सिंह राशि में जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव युवाओं, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। बुध चंद्रमा को अपने शत्रु मानते हैं किंतु चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं। तभी इन दोनों के परस्पर विरोधाभासी प्रभाव दिखते रहते है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। मीन राशि में नीच राशिगत और कन्या राशि में उच्च राशिगत में कहे गए हैं।

सूर्य का कर्क राशि में गोचर

सूर्य देव 16 जुलाई 2021 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 17 अगस्त 2021 तक स्थित रहेंगे। इसके बाद ये अपनी राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, सूर्य देव जगत की आत्मा हैं। वे सभी ग्रहों के राजा हैं। इन्हें सिंह राशि स्वामी माना जाता है। मेष राशि में ये उच्च भाव में होते हैं, तो वहीं तुला राशि में ये नीच के माने जाते हैं। उच्च भाव में ग्रह अधिक मजबूत और बलशाली होते हैं। जबकि नीच राशि में ये कमजोर हो जाते हैं।

25 जुलाई तक इन 4 राशि वालों के आएंगे अच्छे दिन, नौकरी में प्रमोशन के बनेंगे प्रबल योग

मिथुन राशि समेत कई राशियों के लिए जुलाई का महीना शुभ साबित होगा। जुलाई में बुध का गोचर पहली राशि परिवर्तन की घटना होगी। बुध ग्रह अपनी स्वराशि मिथुन में 07 जुलाई 2021 को गोचर करेंगे। बुध का गोचर सुबह 10 बजकर 59 मिनट पर होगा और यह इस राशि में 25 जुलाई तक रहेंगे। बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए खास है। बुध राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों को करियर में सफलता, धन लाभ और शुभ समाचार मिलेंगे। जानिए किन राशि वाले के लिए बुध का राशि परिवर्तन लाएगा अच्छे दिन-

1. मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए बुध गोचर शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको मेहनत का परिणाम मिलेगा। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने की भी संभावना है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। घरवालों का सहयोग प्राप्त होगा।

2. तुला- बुध का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए अच्छे दिन लाएगा। इस दौरान आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। करियर में तरक्की के प्रबल योग बनेंगे। घर में धार्मिक माहौल रहेगा। पूजा-पाठ आदि करा सकते हैं। आय के साधन बढ़ेंगे। वाहन या संपत्ति का सुख मिल सकता है।

3. वृश्चिक- इस राशि के जातकों को प्रमोशन के योग बनेंगे। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। बिजनेस में मुनाफे के पूरे योग बनेंगे। माता-पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छात्रों के लिए समय उत्तम है।

4. धनु- कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय शुभ है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र संबंधी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।

योगिनी एकादशी व्रत के 7 चमत्कारिक फायदे

माह में 2 एकादशियां होती हैं अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियमपूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिकमास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई को है।

1. योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है।

2. यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है।

3. योगिनी एकादशी का व्रत करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है।

4. माना जाता है कि इस व्रत को करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।

5. यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधित रखने से सिद्धि और सफलता मिलती है।

6. कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है।

7. यह एकादशी समस्त आधि-व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रुप, गुण और यश देने वाली कही गई है।

योगिनी एकादशी व्रत की कथा :

अलकापुरी के राजा यक्षराज कुबेर के यहां हेम नामक एक माली कार्य करता था। उस माली का कार्य प्रतिदिन भगवान शिव के पूजन हेतु मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ रमण करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। वह कुबेर की सभा में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया।

श्राप के प्रभाव से हेम माली इधर-उधर भटकता रहा और भटकते-भटकते वह मार्कण्डेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योगबल से उसके दुःखी होने का कारण जान लिया। यह जानकर ऋषि ने उससे कहा कि योगिनी एकादशी का व्रत करो तो श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। माली ने विधिवत रूप से योगिनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ समाप्त हो गया।

घोर संकट के साथ गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे संकट मोचन हनुमान, जान लें मंगलवार के ये 5 अचूक उपाय

मंगलवार का दिन बजरंगबली का होता है। इस दिन हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा की जाती है। हनुमान जी की पूजा के अलग-अलग तरीके होते हैं। लेकिन भक्तों को किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं और भक्त फल की चिंता नहीं करता है। बजरंगबली के लिए उनका मंत्र ही पूजा, भोग और चालीसा है। हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जानिए हनुमान जी को किन चीजों को चढ़ाने से क्या मिलता है लाभ-

1. पान का बीड़ा- एक प्रचलित कहावत है- 'बीड़ा उठाना'। यानी जब कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरे काम की जिम्मेदारी लेना। अगर आपके जीवन में घोर संकट है या कोई ऐसा काम है जो आपके बस का नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है।

2. लौंग, इलाचयी और सुपारी- बजरंगबली को लौंग, इलाचयी और सुपारी प्रिय हैं। शनिवार के दिन इस तीन चीजों को हनुमान जी को अर्पित करने से शनि का कष्ट दूर होने की मान्यता है। इसके अलावा सरसों के तेल में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करने से संकटों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है।

3. नारियल करें अर्पित- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए एक नारियल में सिंदूर लगाएं और उसमें लाल धागा बांधें। यह नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करें।

4. गुड़-चने का भोग- हनुमान जी गुड़ और चने का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस उपाय को करने से मंगल दोष मिटता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर होने की मान्यता है।

5. इमरती- इमरती का भोग संकटमोचन को अतिप्रिय है। कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को इमरती को भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

हंसमुख और मिलनसार होते हैं स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग

27 नक्षत्रों में से स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र है। यह राहु का दूसरा नक्षत्र है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वाति नक्षत्र के सभी चार चरण तुला राशि में होते हैं। जिसके कारण नक्षत्र पर तुला राशि और शुक्र ग्रह का भी प्रभाव पड़ता है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा जातक अच्छी कद-काठी का होता है। ये हंसमुख और मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ये व्यवहार कुशल व शिष्टाचारी होते हैं। ये दयालु प्रवृत्ति और आत्म नियंत्रण वाले होते हैं। जानिए इनके बारे में खास बातें-

हंसमुख और मिलनसार

इस नक्षत्र में जन्मे लोग कभी आलस नहीं करते हैं और अपने काम में निपुण होते हैं। ये बुद्धिमान व अपने कामों को पूरा करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण ये अच्छे-बुरे कामों में भेद नहीं कर पाते हैं। ये लोग जीवन के शुरुआती 25 साल व्यावसायिक रूप से मुसीबतें झेलते हैं।

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी चीजों के बारे में किसी की टिप्पणी पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए न्यायिक व्यवस्था में काम करना लाभकारी रहा है।

आर्थिक स्थिति

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति आमतौर पर अच्छी रहती है। ये धन संचय में भरोसा रखते हैं और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर करियर में सफलता पाते हैं।

वैवाहिक जीवन

स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं रहता है। वैचारिक मतभेद होने के कारण जीवनसाथी के साथ अनबन बनी रहती है।

खाना पकाने का तेल होगा सस्ता, सरकार ने लिया यह महत्वपूर्ण फैसला

नई दिल्ली। एजेंसी

खाना पकाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर अब अंकुश लग सकेगा। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क की मानक दर को घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। अन्य पाम ऑयलों पर यह 37.5 फीसदी होगी। यह निर्णय आज से लागू होकर आगामी 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

सस्ता होगा आयात

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मंगलवार रात को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कच्चे पाम ऑयल पर मानक सीमा शुल्क (BCD) दर संशोधित कर दस फीसदी किया गया है। यह अधिसूचना बुधवार से प्रभावी हो गई है। कच्चे पाम ऑयल पर 10 फीसदी के मूल आयात शुल्क के साथ प्रभावी आयात शुल्क 30.25 फीसदी होगी। इसमें उपकर और अन्य शुल्क शामिल होंगे। जबकि रिफाइंड पाम ऑयल (Refind Palm Oil) के लिए यह शुल्क बुधवार से 41.25 फीसदी हो गया है। सीबीआइसी ने कहा, ''यह अधिसूचना 30 जून, 2021 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।''

इस समय क्या है ड्यूटी की दरें

पाम ऑयल पर वर्तमान में मानक सीमा शुल्क

(BCD) 15 फीसदी है। आरबीडी (Refined, Bleached and Deodorized) पाम ऑयल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीयरिन की अन्य श्रेणियों (क्रूड पाम ऑयल को छोड़कर) पर 45 फीसदी का शुल्क लगता है। सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा, ''लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कच्चे पाम ऑयल पर सीमा शुल्क 35.75 फीसदी से घटाकर 30.25 फीसदी और रिफाइंड पाम ऑयल पर 49.5 फीसदी से घटाकर 41.25 फीसदी कर दिया है। इससे घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी आएगी।''

संतुलन साधने की कोशिश

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा, ''सरकार ने उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों को संतुलित करने की कोशिश की है। इससे गरीबों को तत्काल राहत मिलेगी, जबकि किसानों की रक्षा की जाएगी क्योंकि अक्टूबर में कटाई के मौसम के शुरू होने पर शुल्क फिर से बढ़ाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि रिफाइंड पाम ऑयल के आयात शुल्क में कमी का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का आयात काफी कम होता है। उद्योग निकाय एसईए के आंकड़ों के अनुसार कच्चे पाम ऑयल के उच्च शिपमेंट के चलते मई 2021 में भारत का पाम ऑयल का आयात 48 फीसदी बढ़कर 7,69,602 टन हो गया।

सबसे ज्यादा खपत पाम ऑयल की

देश के कुल खाद्य तेल की खपत में पाम तेल का हिस्सा 60 फीसदी से अधिक है। भारत ने मई 2020 में 4,00,506 टन पाम ऑयल का आयात किया था। मई 2021 में देश का वनस्पति तेलों का कुल आयात 68 फीसदी बढ़कर 12.49 लाख टन हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 7.43 लाख टन था।

आयात की तीसरी बड़ी कमोडिटी

कच्चा तेल और सोने के बाद पाम ऑयल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयात किया जाने वाला जिंस है। भारत खाद्य तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है, और मलेशिया और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों से सालाना लगभग 1.5 करोड़ टन खाद्य तेल खरीदता है। सरकार ने इस माह की शुरुआत में पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य में भी 112 डालर प्रति टन तक कमी की थी। इससे भी घरेलू कीमतों को कम रखने में सहायक माना गया।

पेट्रोल और खाद्य तेलों के बाद अब दूध भी हुआ महंगा, अमूल ने बढ़ाई कीमत

अहमदाबाद। *एजेंसी*

पेट्रोल और डीजल तथा खाद्य तेलों की महंगाई पहले से ही आम आदमी की कमर तोड़े हुए है। अब दूध भी उसके पीछे पीछे है। देश में दूध का कारोबार करने वाले सबसे बड़े संगठन गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने अपने सभी तरह के दूध की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। सभी तरह के दूध की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। यह फैसला कल, यानी एक जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा।

एक साल सात महीने बाद बढ़ी दूध की कीमतें

गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने बुधवार को यह जानकारी दी। संगठन की तरफ से बताया गया कि अमूल दूध की कीमतों में एक जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। अमूल ब्रांड नाम के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी ने कहा कि लगभग एक साल और सात महीने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण जरूरी हो गई थी।

क्यों बढ़ी कीमतें

आर एस सोढ़ी ने कहा, ''अमूल दूध की कीमतों में कल से पूरे भारत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। नई कीमतें सभी अमूल दूध ब्रांडों जैसे सोना, ताजा, शक्ति, टी-स्पेशल, साथ ही गाय और भैंस के दूध पर भी लागू होंगी।'' सोढ़ी ने कहा कि खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण दूध की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पैकेजिंग की लागत में 30 से 40 प्रतिशत, परिवहन लागत में 30 प्रतिशत और ऊर्जा लागत में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके चलते उत्पादन लागत बढ़ गई है।

आम आदमी पहले से ही परेशान

इन दिनों खाद्य तेलों की कीमतें चरम पर हैं। कभी करीब एक सौ रुपये किलो बिकने वाला सरसों तेल अभी 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल में आए दिन कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो ही रही है। ऐसे में दूध की बढ़ी कीमत से लोगों को रोज ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

टाटा मोटर्स को इंडियन ऑयल से हाइड्रोजन आधारित 15 बसों का ऑर्डर मिला

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि उसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) से 15 हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों का ऑर्डर मिला है। टाटा मोटर्स ने कहा कि आईओसीएल ने दिसंबर 2020 में हाइड्रोजन आधारित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) ईंधन सेल बसों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की थीं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि सभी 15 बसों को सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर की तारीख से 144 सप्ताह के भीतर सौंप दिया जाएगा। टाटा मोटर्स ने कहा कि बसों की आपूर्ति के अलावा वह वाणिज्यिक वाहनों के लिए ईंधन सेल प्रौद्योगिकी की क्षमता का अध्ययन करने के लिए आईओसीएल के अनुसंधान और विकास केंद्र के साथ भी सहयोग करेगा।

गडकरी ने कहा, एमएसएमई को रेटिंग देने की प्रणाली शुरू हो

नयी दिल्ली। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने क्षेत्र के लिए एक रेटिंग प्रणाली बनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड बनाने की बात कही है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को रेटिंग्स देने के लिए आसान और पारदर्शी तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छे कारोबार तथा बेहतर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिकॉर्ड वाले एमएसमएई को रेटिंग से उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारतीय उद्योग में निवेश करना चाहती है और एक प्रभावी रेटिंग प्रणाली के जरिये एमएसएमई को विदेशों से अच्छा निवेश मिल सकता है। गडकरी ने योजनाओं की निगरानी के लिए डैशबोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव किया। इससे निर्णय प्रक्रिया में देरी को रोका जा सकेगा। उन्होंने सिडबी से तीन महीने में फैसला करने और क्षेत्र को समर्थन उपलब्ध कराने को कहा। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का हिस्सा करीब 30 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे टूटा

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी मुद्रा में तेजी और कच्चे तेल के भाव में बढ़ोतरी के चलते भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच पैसे की गिरावट के साथ 74.28 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 74.23 पर खुला और फिर गिरावट दर्ज करते हुए 74.28 तक आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले पांच पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.23 पर बंद हुआ था। इस बीच वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.41 प्रतिशत बढ़कर 75.07 डॉलर प्रति बैरल हो गया। छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 92.05 पर अपरिवर्तित था।

सरकार ने कच्चे पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर की 10%, सितंबर तक लागू रहेगी नई दर

नई दिल्ली। एजेंसी

पाम तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। नई दर 30 जून 2021 से लागू होकर 30 सितंबर 2021 तक प्रभाव में रहेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में पाम तेल की कीमतें कम हो सकती हैं।

सरकार ने घटाई इंपोर्ट ड्यूटी

केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए मंगलवार को कच्चे पाम तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को घटाकर 10 फीसदी कर दिया। वहीं दूसरे पाम तेलों पर यह 37.5 फीसदी होगी। यह निर्णय इस साल 30 सितंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (ण्ँघ्ण) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि कच्चे पाम तेल पर मानक सीमा शुल्क (ँण्ॅ) दर संशोधित कर 10 प्रतिशत किया गया है। सीबीआइसी ने कहा कि, ''यह अधिसूचना 30 जून, 2021 से प्रभावी होगी और 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी।''

क्रूड पाम तेल पर अभी मानक सीमा शुल्क (बीसीडी) 15 फीसदी है जबकि आरबीडी पाम ऑयल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम स्टीयरिन की दूसरी कैटेगरी (क्रूड पाम ऑयल को छोड़कर) पर 45 फीसदी बीसीडी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि कच्चे पाम तेल (ण्इ्ध) पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक इस पर कृषि उपकर (सेस) आदि पहले की तरह लागू रहेंगे जिससे कि प्रभावी आयात शुल्क दर 30.25 फीसदी तक होगी। इससे पहले प्रभावी दर 35.75 फीसदी थी। दरअसल भारत के कुल खाद्य तेल की खपत में पाम तेल का हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा है। कच्चा तेल और सोने के बाद पाम तेल भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयात होने वाली जिंस है।

भारत में अप्रैल में 27,700 शिकायतें मिलीं, 59,000 से अधिक सामग्री हटाईं गईं: गूगल

नयी दिल्ली। एजेंसी

गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा कि उसे भारत में इस साल अप्रैल में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से स्थानीय कानूनों या व्यक्तिगत अधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित 27,700 से अधिक शिकायतें मिलीं, जिसके चलते 59,350 सामग्रियों को हटाया गया। गूगल ने 26 मई से लागू हुए आईटी नियमों के तहत अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी की।

नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल मंचों को हर महीने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण होगा। रिपोर्ट में कई ऐसे संचार लिंक या जानकारी का ब्यौरा भी दिया गया है, जिन्हें

गूगल ने स्वचालित उपकरणों की मदद से हटा दिया है या पहुंच को अक्षम कर दिया।

गूगल के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी का दुनिया भर से मिलने वाले विभिन्न अनुरोधों के संबंध में पारदर्शिता का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, "इन सभी अनुरोधों का निरीक्षण किया गया और 2010 से हमारी मौजूदा पारदर्शिता रिपोर्ट में इन्हें शामिल किया गया है। यह पहली बार है जब हम (भारत के) नए आईटी नियमों के अनुसार मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, और अधिक विवरण प्रकाशित करना जारी रखेंगे क्योंकि हम भारत के लिए अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को बेहतर बना रहे हैं।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेटा संस्करण और सत्यापन के लिए लगने वाले समय को देखते हुए आंकड़े दो महीने बाद आएंगे।

फिर कोरोना का कहर

ब्रिटेन में पांच महीने बाद मिले 22 हजार से ज्यादा मरीज, इन देशों ने लगाई यात्रा पाबंदी

एजेंसी

ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में मंगलवार को पांच महीने में पहली बार एक दिन में 22 हजार से अधिक कोरोना मरीज मिले और तीन मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले 30 जनवरी, 2021 को 23,108 नए मरीज मिले थे। इसी के साथ ब्रिटेन में एक्टिव केस बढ़कर 3,07,776 पहुंच गए हैं। स्पेन और हांगकांग ने ब्रिटेन में फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने यहां ब्रिटिश यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

ब्रिटिश सरकार अब छात्रों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों के सेल्फ आइसोलेशन से माता-पिता परेशान हो गए हैं। बच्चों की शिक्षा भी बाधित हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री निक गिब ने मंगलवार को बताया कि हम बच्चों के सेल्फ आइसोलेशन के बजाय डेली कॉन्टैक्ट टेस्टिंग पर जोर देना चाहते हैं। सरकार 19 जुलाई के पहले इस पर फैसला करेगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन को खत्म करने को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है।

सेल्फ आइसोलेशन खत्म करने की मांग

बता दें कि ब्रिटेन में 17 जून तक 1.70 लाख से अधिक छात्र सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। ये छात्र ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए थे, जिन्हें कोरोना हुआ था। ये सरकार अनुदानित स्कूलों की छात्र संख्या का दो फीसदी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार और बच्चों के माता-पिता दबाव में आ गए थे। माता-पिता की मांग है कि बच्चों का सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर दिया जाए। इससे उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही है। वे नौकरी और कामकाज के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं।

इन देशों ने लगाया प्रतिबंध

जर्मनी के बाद अब हांगकांग ने भी ब्रिटेन की उड़ानों के अपने यहां आने पर रोक लगा दी है। वहीं स्पेन ने भी ब्रिटेन को प्रतिबंध मुक्त यात्रा सूची से हटा दिया है। नए आदेश के अनुसार, स्पेन में सिर्फ टीकाकरण करा चुके या कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वाले ब्रिटिश यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन में अब तक 4,775,301 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 128,126 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4,322,070 लोग ठीक हो गए हैं।

वालमार्ट ने एमएसएमई की कोविड-19 संबंधित सहायता के लिए 'वृद्धि केयर' पहल शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक रिटेल कंपनी वालमार्ट ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में कार्यरत लोगों और उनके परिवार के सदस्यों की कोविड-19 से जुड़ी सहायता के लिए सोमवार को वृद्धि केयर्स पहल की शुरुआत की। एक बयान के मुताबिक पहल के तहत कंपनी इन उद्यमों में कार्यरत लोगों और उनके

परिवार के सदस्यों की टेलीकेयर सेवाओं एवं स्वास्थ्य परामर्श प्रदान कर सहायता करेगी। कंपनी महामारी संबंधी व्यापार सुझाव और संसाधन तक पहुंच भी प्रदान करेगी। वालमार्ट ने निशुल्क टेलीकेयर सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठन 'स्वाति' के साथ समझौता किया है। पहल के तहत फोन के जरिए डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों तक दूर रहते हुये पहुंच प्रदान की जाएगी। बयान में कहा गया, 'कार्यक्रम के तहत टीका दिशानिर्देशों, घरों में क्वारंटीन की प्रक्रिया और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने से जुड़ी नवीनतम सूचना मुहैया करायी जाएगी। यह सूचना अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में दी जाएगी'

कोरोना का कहर: अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 जुलाई तक बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना महामारी के कारण शेड्यूल्ड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एक बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर

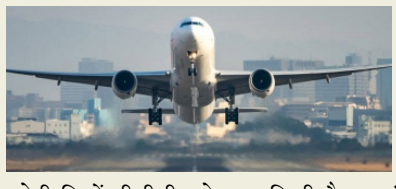

प्रतिबंध 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। यह रोक उन अंतरराष्ट्रीय कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिन्हें डीजीसीए ने अनुमति दी है। हालांकि कुछ चुने हुए रूट्स पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। हालांकि घरेलू उड़ानों को मई 2020 में कुछ शर्तों के साथ बहाल कर दिया गया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रही। उर्ण मार्च 2020 के बाद से कई बार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक बढ़ा चुका है। सरकार ने महामारी के कारण दुनिया अलग-अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया था।

आधार कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट, सभी के लिए होगा लागू

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट संख्या जिसे हम आधार कार्ड (Aadhaar Card) के नाम से जानते हैं, को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना अब पहले से और अधिक आसान हो गया है। यूआईडीएआई ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर एक डायरेक्ट लिंक eaadhaar.uidai.gov.in शेयर किया है। इस लिंक पर क्लिक कर आप कहीं भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे अब आधार को साथ रखने या उससे संबंधी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।

यूआईडीएआई का ट्वीट

यूआईडीएआई ने अपने आधिकारिक

ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस सुविधा की जानकारी दी है। आधार कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक साझा करते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि अपना आधार https://eaadhaar.uidai.gov.in से कभी भी कहीं भी डाउनलोड करें। आप नियमित आधार डाउनलोड करना चुन सकते हैं।

मास्क्ड आधार कार्ड

UIDAI ने हाल ही में आधार का नया फीचर लांच किया, जिसे Masked Aadhaar कहा गया है। चूंकि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, लेकिन इस मास्क्ड Aadhaar की मदद से आप आधार के शुरुआती 8 अंक को छुपा सकते हैं। यानी Masked Aadhaar में आपको जरूरी के आखिरी के 4 अंक ही दिखाई देंगे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।